



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3389]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 17, 2019/आश्विन 25, 1941
No. 3389]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 17, 2019/ASVINA 25, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2019

का.आ. 3727(अ).—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में नाभिकीय ईंधन और संघटक, भारी पारी और संबद्ध रसायन तथा आण्विक ऊर्जा का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले स्थापनों की सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 28 के अंतर्गत आती हैं, को लोक उपयोगिता सेवा घोषित किया जाना चाहिए;

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त औद्योगिक स्थापनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 अप्रैल, 2019 से भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1633(अ) तारीख 24 अप्रैल, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 24 अप्रैल, 2019 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छह मास की अवधि के लिए अंतिम बार लोक उपयोगिता सेवा घोषित किया है;

और केंद्रीय सरकार का यह मत है कि लोक हित उक्त औद्योगिक स्थापनों को लोक उपयोगिता सेवा प्रास्थिति की छह मास की और अवधि के लिए विस्तार करने की अपेक्षा करता है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि उक्त औद्योगिक स्थापनों में लगी हुई सेवाएं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 अक्टूबर, 2019 से लोक उपयोगिता सेवा होंगी।

[फा. सं. एस.-11017/3/1997-आईआर(पीएल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th October, 2019

S.O. 3727(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the industrial establishments manufacturing or producing Nuclear Fuel and components, Heavy Water and Allied Chemicals and Atomic Energy, which are covered under item 28 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industrial establishments to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 24th April, 2019 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1633(E), dated the 24th April, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 24th April, 2019.

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industrial establishments for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the said industrial establishments to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 24th October, 2019.

[F. No. S-11017/3/ 1997-IR(PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.